

Rajasthali Law Institute

Prelims test series

CRPC PAPER-6

(Chapter 25 to 30)

1) दण्ड प्रक्रिया संहिता के अंतर्गत विकृत-चित्त अभियुक्त को कुछ विधिक संरक्षण दिए गए हैं। यह प्रावधान पाए जाते हैं-(U.P. A.P.O. 2015)

- (a) धारा 328 में
- (b) धारा 331 में
- (c) धारा 334 में
- (d) उक्त सभी धाराओं में

1) Under the Code of Criminal Procedure, some legal protections have been given to the unsound mind accused. These provisions are found-

- (a) In section 328
- (b) In section 331
- (c) In section 334
- (d) In all the above sections

2) दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 345 के अधीन न्यायालय को अपनी अवमानना के अपराध का संज्ञान करने तथा अभियुक्त को दण्डित

करने का अधिकार प्राप्त है, किन्तु इस धारा में कार्यवाही की जा सकती है-(**M.P. A.P.O. 1993**)

- (a) केवल सिविल या दाण्डिक न्यायालय द्वारा, राजस्व न्यायालय द्वारा नहीं
- (b) केवल उसी स्थिति में जबकि अवमानना का अपराध न्यायालय की दृष्टिगोचरता या उपस्थिति में किया जाता है
- (c) उस स्थिति में जबकि अवमानना का अपराध न्यायालय के बाहर एवं उसकी दृष्टिगोचरता से अन्यथा किया जाता है
- (d) किसी भी समय, धारा 468 में उल्लिखित अवधि की समाप्ति के पूर्व की जा सकती है

2) Under Section 345 of the Code of Criminal Procedure, the court has the right to take cognizance of the offence of contempt and to punish the accused, but action can be taken under this section -

- (a) Only by civil or criminal court, not by revenue court
- (b) only where the offence of contempt is committed in the perceptibility or presence of the Court
- (c) In the case when the offence of contempt is committed outside the court and otherwise than within its perceptibility
- (d) At any time before the expiry of the period mentioned in section 468

3) जब कोई व्यक्ति न्यायालय में प्रश्न का उत्तर देने या दस्तावेज पेश करने से मना कर देता है, तो उसे दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 की धारा

349 में कितने कारावास का दण्ड दिया जा सकता है?(Uttarakhand (CJ) 2016

U.P.A.P.O. 2005, 2007)

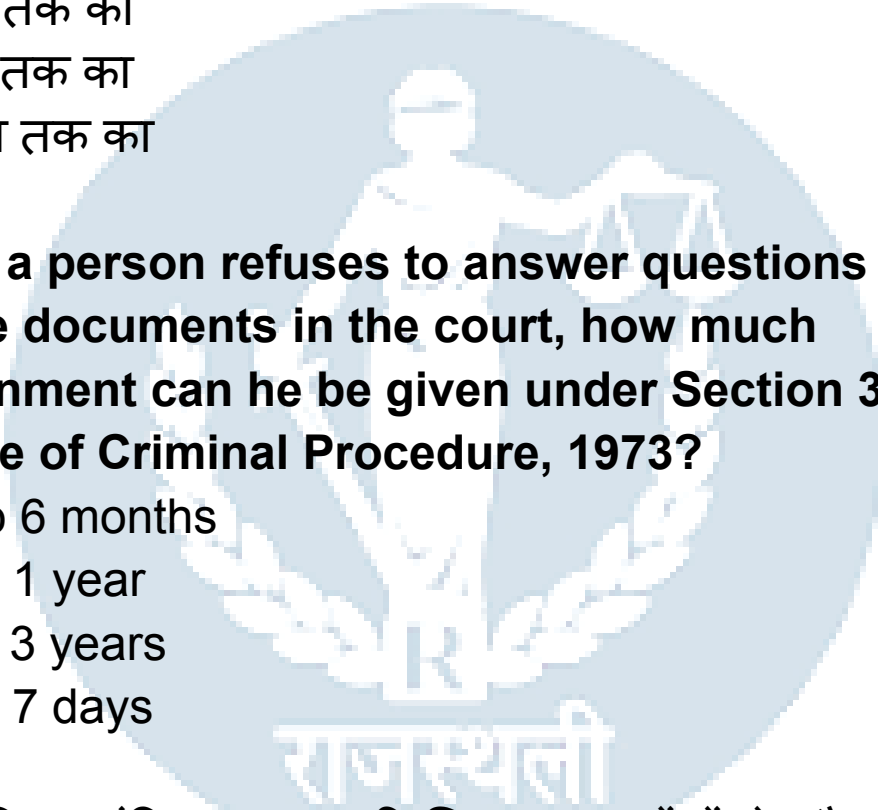
- (a) 6 मास तक का
- (b) 1 वर्ष तक का
- (c) 3 वर्ष तक का
- (d) 7 दिन तक का

3)When a person refuses to answer questions or produce documents in the court, how much imprisonment can he be given under Section 349 of the Code of Criminal Procedure, 1973?

- (a) Up to 6 months
- (b) up to 1 year
- (c) up to 3 years
- (d) up to 7 days

4)दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 की निम्न धाराओं में से कौन-सी धारा में निर्णय की भाषा एवं विषय-वस्तु का उपबन्ध किया गया है?(U.P. (CJ) 2016)

- (a) धारा 353 में
- (b) धारा 354 में
- (c) धारा 355 में
- (d) धारा 356 में



RAJASTHALI
LAW INSTITUTE

4) In which of the following sections of the Code of Criminal Procedure, 1973, the language and content of the judgment is provided?

- (a) In section 353
- (b) In section 354
- (c) In section 355
- (d) In section 356

5)दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 354 (5) के अंतर्गत जब किसी व्यक्ति को मृत्युदण्ड दिया जाता है, यह दण्डादेश निर्देश देगा कि-(Raj. J.L.O. 2014)

- (a) फांसी लगाकर मृत्यु दी जाए।
- (b) उसे गर्दन में फांसी लगाकर मृत्यु दी जाए।
- (c) उसे गर्दन में फांसी लगाकर तब तक लटकाया जाए जब तक उसकी मृत्यु न हो जाए।
- (d) फांसी तब तक लगाई जाए जब तक उसकी मृत्यु न हो जाए।

5) Under Section 354 (5) of the Code of Criminal Procedure, when a person is given death sentence, this sentence will direct That-

- (a) Death should be given by hanging.
- (b) He should be given death by hanging by neck.
- (c) He should be hanged by the neck until he dies.
- (d) He should be hanged until he dies.

6)दण्ड विधि (संशोधन) अधिनियम, 2013 द्वारा कौन-सा प्रावधान दं.प्र.सं. में नहीं जोड़ा गया है?(M.P.H.J.S. 2016)

- (a) धारा 357-C दं.प्र.सं.
- (b) धारा 198-B दं.प्र.सं.
- (c) धारा 357-B दं.प्र.सं.
- (d) धारा 168-A दं.प्र.सं.

6) Which provision has not been added by the Criminal Law (Amendment) Act, 2013 in criminal procedure code ?

- (a) Section 357-C CrPC
- (b) Section 198-B CrPC
- (c) Section 357-B CrPC
- (d) Section 168-A CrPC

7) हाल ही में निम्न प्रकरणों में से किस एक में सर्वोच्च न्यायालय ने तेजाब के हमले में घायल व्यक्ति के चिकित्सीय इलाज के लिए निर्देश जारी किए हैं?(U.P. A.P.O. 2015)

- (a) म.प्र. राज्य बनाम मदनलाल
- (b) लक्ष्मी बनाम भारत संघ
- (c) जगदार सिंह बनाम हरियाणा राज्य
- (d) उपर्युक्त में से कोई नहीं

7) Recently, in which one of the following cases has the Supreme Court issued instructions for the medical treatment of a person injured in an acid attack?

- (a) M.P. State vs Madanlal
- (b) Lakshmi vs Union of India
- (c) Jagdar Singh vs. State of Haryana

(d) None of the above

8) सभी चिकित्सालय, चाहे शासकीय या निजी, एसिड अटैक एवं बलात्संग की पीड़ित को निःशुल्क प्राथमिक चिकित्सा एवं चिकित्सकीय उपचार उपलब्ध कराने के लिए कर्तव्यबद्ध हैं-(M.P. (CJ) (S-II) 2018)

- (a) दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 357बी के अंतर्गत
- (b) दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 357सी के अंतर्गत
- (c) दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 357ए के अंतर्गत
- (d) दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 53ए (2) के अंतर्गत

8) All hospitals, whether government or private, are duty bound to provide free first aid and medical treatment to the victims of acid attack and rape.

- (a) Under section 357B of the Code of Criminal Procedure
- (b) Under section 357C of the Code of Criminal Procedure
- (c) Under section 357A of the Code of Criminal Procedure
- (d) Under section 53A (2) of the Code of Criminal Procedure

9) दंड प्रक्रिया संहिता की निम्नलिखित कौन-सी धारा 'पीड़ित प्रतिकर स्कीम' का उपबंध नहीं करती है?(Uttarakhand (CJ) 2019)

- (a) धारा 357
- (b) धारा 357A
- (c) धारा 357C
- (d) धारा 357B

9) Which of the following sections of the Code of Criminal Procedure does not provide for 'Victim Compensation Scheme'?

- (a) Section 357
- (b) Section 357A
- (c) Section 357C
- (d) Section 357B

10) दण्ड विधि (संशोधन) अधिनियम 2013 प्रवृत्त हुआ है-(Uttarakhand (CJ) 2014)

- (a) 6 अप्रैल, 2013 को
- (b) 3 फरवरी, 2013 को
- (c) 7 जनवरी, 2013 को
- (d) 5 मार्च, 2013 को

10) Criminal Law (Amendment) Act 2013 has come into force-

- (a) On April 6, 2013
- (b) On February 3, 2013
- (c) January 7, 2013
- (d) On March 5, 2013

11) दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973 की किस धारा में पीड़ितों के उपचार हेतु अपराध विधि (संशोधन) अधिनियम 2013 से जोड़े गए हैं-(Uttarakhand (CJ) 2014

U.P. A.P.O. 2015)

- (a) धारा 198 B में

- (b) धारा 357 B में
- (c) धारा 357 C में
- (d) उपरोक्त में से कोई नहीं

11) Which section of the Code of Criminal Procedure 1973 has been added by Criminal Law (Amendment) Act 2013 for the treatment of victims?

- (a) In section 198B
- (b) In section 357B
- (c) In Section 357 C
- (d) None of the above

12) धारा 357 क (2) दण्ड प्रक्रिया संहिता के अंतर्गत प्रतिकर की मात्रा का निर्धारण कौन करेगा? (M.P.A.D.P.O. 2015 M.P. (CJ) 2011, 2013)

- (a) सेशन न्यायाधीश
- (b) उपखण्ड मजिस्ट्रेट
- (c) जिला मजिस्ट्रेट
- (d) राज्य या जिला विधि सेवा प्राधिकरण

12) Who will determine the amount of compensation under Section 357 A (2) of the Code of Criminal Procedure?

- (a) Session Judge
- (b) Sub-Divisional Magistrate
- (c) District Magistrate
- (d) State or District Legal Services Authority

13)निम्नलिखित में से कौन सी धारा 'पीड़ित प्रतिकर स्कीम से संबंधित है?(Bihar H.J.S. 2019)

- (a) धारा 280-बी सीआरपीसी।
- (b) धारा 287-डी सीआरपीसी।
- (c) धारा 357-ए सी.आर.पी.सी.
- (d) धारा 289-बी सीआरपीसी।

13)Which of the following Section deals with victim compensation scheme?

- (a) Section 280-B Cr.P.C.
- (b) Section 287-D Cr.P.C.
- (c) Section 357-A Cr.P.C.
- (d) Section 289-B Cr.P.C.

14)"आहत प्रतिकर योजना" दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 357 (क) में किस संशोधन अधिनियम से जोड़ी गई है?(Raj. A.P.O. 2011 Jharkhand (CJ) 2012 Uttarakhand (CJ) 2016)

- (a) एक्ट 25 के 2005 संशोधन से
- (b) एक्ट 5 के 2009 संशोधन से
- (c) एक्ट 45 के 1978 संशोधन से
- (d) एक्ट 2 के 2006 संशोधन से

14) “Injured Compensation Scheme” has been added to which Amendment Act in Section 357 (a) of the Code of Criminal Procedure, 1973?

- (a) By the 2005 amendment of Act 25
- (b) By 2009 amendment of Act 5
- (c) 1978 amendment of Act 45
- (d) By the 2006 amendment of Act 2

15). दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 की किस धारा में न्यायालय अभियुक्त को आदेश दे सकता है कि वह क्षतिपूर्ति का भुगतान करे?(Jharkhand A.P.P. 2018)

- (a) धारा 354
- (b) धारा 355
- (c) धारा 356
- (d) धारा 357

15). Under which section of the Code of Criminal Procedure, 1973, the court can order the accused to pay compensation?

- (a) Section 354
- (b) Section 355
- (c) Section 356
- (d) Section 357

16). दंड प्रक्रिया संहिता की निम्नलिखित में से कौन-सी धारा यह प्रावधानित करती है कि कोई न्यायालय जब उसने किसी मामले को निपटाने के लिए अपने निर्णय या अंतिम आदेश पर हस्ताक्षर कर

दिए हैं, तब लिपिकीय या गणितीय मूल को ठीक करने के सिवाय उसमें कोई परिवर्तन नहीं करेगा या उसका पुनर्विलोकन नहीं करेगा?(M.P. (CJ) (S-II) 2019)

- (a) धारा 463
- (b) धारा 361
- (c) धारा 362
- (d) धारा 363

16).Which of the following sections of the Code of Criminal Procedure provides that a Court,when it has signed its judgment or final order disposing of a case, shall not alter or review the same except to correct a clerical or arithmetical error.

- (a) Section 463
- (b) Section 361
- (c) Section 362
- (d) Section 363

17) निर्णय सुनाए जाते समय किस मामले में अभियुक्त, की उपस्थिति अभिमुक्त की जा सकती है?(U.P. A.P.O. 2005, 2007)

- (a) जब न्यायालय ने अभियुक्त को व्यक्तिगत उपस्थिति से पूर्व ही अभिमक्ति प्रदान कर दी हो
- (b) जब निर्णय दोषमक्ति का हो
- (c) (a) तथा (b) दोनों में
- (d) उपरोक्त में से कोई नहीं

17) In which case the presence of the accused can be dispensed when the judgment is pronounced?

- (a) When the court has already granted dispensation to the accused before personal appearance
- (b) When the judgement is of acquittal
- (c) In both (a) and (b)
- (d) None of the above

18) राजस्थान राज्य में एक विचारण न्यायालय अपना निर्णय अंग्रेजी में पारित करता है। विधि के किस प्रावधान के अंतर्गत अभियुक्त इस निर्णय की हिंदी भाषा में रूपांतरित प्रति मांग सकता है?(Raj(JS) 2019)

- (a) दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 353
- (b) दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 362
- (c) दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 364
- (d) दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 363

18) A trial court in the state of Rajasthan passes its judgment in English. Under which provision of law can the accused ask for a translated copy of this judgment in Hindi language?

- (a) Section 353 of the Code of Criminal Procedure
- (b) Section 362 of the Code of Criminal Procedure
- (c) Section 364 of the Code of Criminal Procedure
- (d) Section 363 of the Code of Criminal Procedure

19)दंड प्रक्रिया संहिता की निम्नलिखित धाराओं में से कौन-सी धारा अपराधियों को अच्छे आचरण पर परीवीक्षा पर छोड़े जाने से संबंधित है?(Uttarakhand (CJ) 2018)

- (a) धारा 260
- (b) धारा 350
- (c) धारा 356
- (d) धारा 360

19)Which of the following sections of the Code of Criminal Procedure deals with the release of offenders on probation on good conduct?

- (a) Section 260
- (b) Section 350
- (c) Section 356
- (d) Section 360

20)दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 360 के अंतर्गत सदाचरण की परीवीक्षा पर किसे छोड़ा जा सकता है?(M.P. A.P.O. 2008)

- (a) जो व्यक्ति इक्कीस वर्ष से कम आयु का नहीं है
- (b) जो व्यक्ति इक्कीस वर्ष से कम आयु का है
- (c) कोई स्त्री
- (d) उपर्युक्त सभी

20)Who can be released on probation of good conduct under Section 360 of the Code of Criminal Procedure?

- (a) A person who is not less than twenty-one years of age
- (b) A person who is under twenty-one years of age

- (c) A woman
- (d) All of the above

21)परिवीक्षा पर किसे नहीं छोड़ा जा सकता?(Jharkhand (CJ) 2012)

- (a) एक व्यक्ति जो 21 वर्ष से अधिक आयु का है और ऐसे अपराध के लिए दोषसिद्ध किया जाता है जिसकी सजा 7 वर्ष है
- (b) एक व्यक्ति जो 21 वर्ष से कम आयु का है और ऐसे अपराध के लिए दोषसिद्ध किया जाता है जिसकी सजा आजीवन कारावास है
- (c) एक स्त्री जो ऐसे अपराध के लिए दोषसिद्ध की जाती है जिसकी सजा 10 वर्ष है
- (d) उपर्युक्त में से कोई नहीं

21)Who cannot be released on probation?

- (a) A person who is above 21 years of age and is convicted of an offence punishable with imprisonment for 7 years
- (b) a person who is under 21 years of age and is convicted of an offence punishable with imprisonment for life
- (c) A woman who is convicted of an offence punishable with imprisonment for 10 years
- (d) None of the above

22)खाद्य अपमिश्रण अधिनियम के तहत किसी अपराध के लिए दोषसिद्ध किए गए व्यक्ति को परिवीक्षा अधिनियम तथा दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 360 लागू होगी, जब व्यक्ति की आयु कितनी हो?(Chhattisgarh (CJ) 2007)

- (a) 18 वर्ष से कम
- (b) 14 वर्ष से कम
- (c) 22 वर्ष से कम
- (d) 19 वर्ष से कम

22) What is the age of the person when the Probation Act and Section 360 of the Code of Criminal Procedure will apply to a person convicted of an offence under the Food Adulteration Act?

- (a) less than 18 years
- (b) less than 14 years
- (c) less than 22 years
- (d) less than 19 years

23)दण्ड प्रक्रिया संहिता की किस धारा के अंतर्गत निराधार गिरफ्तार करवाए गए व्यक्तियों को प्रतिकर देने का उपबन्ध है?(Uttarakhand (CJ) 2011, 2015)

- (a) धारा 357
- (b) धारा 358
- (c) धारा 357ए
- (d) धारा 360

23) Under which section of the Code of Criminal Procedure, there is a provision for giving compensation to persons who have been groundlessly arrested ?

- (a) Section 357

- (b) Section 358
- (c) Section 357A
- (d) Section 360

24) निराधार गिरफ्तार करवाए गए व्यक्ति को इस संबंध में उसके समय की हानि और व्यय के लिए: रुपये से अनधिक इतना प्रतिकर, जितना मजिस्ट्रेट ठीक समझे, मामले की सुनवाई करने वाले मजिस्ट्रेट द्वारा गिरफ्तार कराने वाले व्यक्ति से दिलाया जा सकेगा। **(M.P. (CJ) 2002)**

- (a) एक सौ
- (c) तीन सौ
- (b) पांच सौ
- (d) एक हजार

24)) A person who has been arrested without any reason, may be given such compensation, as the Magistrate thinks fit, for the loss of his time and expense in this regard, from the person who caused the arrest, by the Magistrate hearing the case.

- (a) one hundred
- (c) three hundred
- (b) five hundred
- (d) one thousand

25) दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 358 के अंतर्गत जुर्माने का भुगतान न करने पर किस अधिकतम व्यतिक्रम का दण्डादेश पारित किया जा सकता है? **(Uttarakhand (CJ) 2014)**

- (a) 60 दिन का
- (b) 30 दिन का
- (c) 90 दिन का
- (d) 120 दिन का

25) Under Section 358 of the Code of Criminal Procedure 1973, what is the maximum punishment which can be passed for default of non-payment of fine?

- (a) 60 days
- (b) 30 days
- (c) 90 days
- (d) 120 days

26) निम्नलिखित कथनों में से कौन-सा कथन गलत है? एक असंज्ञेय अपराध के बाबत अभियोग पत्र प्रस्तुत होने पर यदि न्यायालय अभियुक्त को दोषी निर्णीत करे तो न्यायालय-(M.P. (CD) 1986)

- (a) अभियुक्त को कारावास का दण्ड दे सकता है
- (b) अभियुक्त को अर्थदण्ड कर सकता है
- (c) अभियुक्त से अभियोगी को उनके द्वारा प्रकरण में किया गया व्यय या उसका अंश दिला सकता है
- (d) अभियुक्त को कारावास तथा अर्थदण्ड दोनों से दण्डित कर सकता है

26) Which of the following statements is incorrect? If the court, on presentation of a charge sheet in respect

of a non-cognizable offence, finds the accused guilty, the court shall-

- (a) Can sentence the accused with imprisonment
- (b) Can fine the accused
- (c) The accused can recover from the plaintiff the expenses incurred by him in the case or his part thereof.
- (d) The accused can be punished with both imprisonment and fine.

27)दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 की निम्न में से कौन-सी धारा यह प्रावधान करती है कोई न्यायालय निर्णय पर हस्ताक्षर करने के पश्चात उसे परिवर्तित नहीं करेगा?(Uttarakhand A.P.O. 2016

Uttarakhand (CJ) 2011, 2015

U.P. A.P.O. (Spl.) 2007)

- (a) धारा 360
- (b) धारा 361
- (c) धारा 362
- (d) धारा 462

27)Which of the following sections of the Code of Criminal Procedure, 1973 provides that a court will not change the decision after signing it?

- (a) Section 360
- (b) Section 361
- (c) Section 362
- (d) Section 462

28) दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 372 के परंतुक के अनुसार पीड़ित को न्यायालय द्वारा पारित आदेश से अपील प्रस्तुत करने का अधिकार नहीं है -(M.P. (CJ) (S-I) 2018)

- (a) अभियुक्त को दोषमुक्त करने
- (b) न्यूनतम अपराध के लिए दंडसिद्ध करने
- (c) अपर्याप्त प्रतिकर अधिरोपित करने
- (d) अपर्याप्त दंडादेश पारित करने

28) According to the proviso to Section 372 of the Code of Criminal Procedure, the victim does not have the right to present an appeal from the order passed by the court -

- (a) To acquit the accused
- (b) To be convicted for the lesser offence
- (c) Imposing inadequate compensation
- (d) Passing inadequate sentence

29) मृत्यु दण्ड की पुष्टि किए जाने में उच्च न्यायालय के कम से कम कितने न्यायाधीशों के हस्ताक्षर की आवश्यकता है? (Uttarakhand (CJ) 2012)

Raj. J.L.O. 2014)

- (a) एक
- (b) दो
- (c) तीन
- (d) पांच

29) Signatures of at least how many High Court judges are required to confirm the death penalty?

- (a) one
- (b) two
- (c) three
- (d) five

30) सत्र न्यायालय द्वारा मृत्युदण्ड की पुष्टि के लिए उच्च न्यायालय भेजे जाने पर उच्च न्यायालय : (Uttarakhand (CJ) 2009

Raj. J.L.O. 2014)

- (a) दण्डादेश की पुष्टि कर सकता है।
- (b) दण्डादेश को रद्द कर सकता है।
- (c) विधि-सम्मत अन्य दण्डादेश पारित कर सकता है।
- (d) उपर्युक्त सभी।

30) When the Sessions Court sends to the High Court for confirmation of the death sentence then High Court?

- (a) Can confirm the sentence.
- (b) Can cancel the sentence.
- (c) Can pass any other sentence as per law.
- (d) All of the above.

31) दं.प्र.सं. की निम्नलिखित में से कौन-सी धारा दण्डादेश को पुष्ट करने या दोषसिद्धि को रद्द करने की उच्च न्यायालय की शक्ति का प्रावधान करती है? (Uttarakhand (CJ) 2013

Uttarakhand (CJ) 2019)

- (a) धारा 366
- (b) धारा 367
- (c) धारा 369
- (d) धारा 368

31) Which of the following sections of the Crpc provides for the power of the High Court to confirm the sentence or annul the conviction?

- (a) Section 366
- (b) Section 367
- (c) Section 369
- (d) Section 368

32) मृत्युदण्डादेश की पुष्टि की कार्यवाही में उच्च न्यायालय को अधिकार है कि वह (Uttarakhand (CJ) 2015)

- (a) केवल मृत्युदण्डादेश की पुष्टि करे या अन्य दण्डादेश दे
- (b) केवल अभियुक्त को किसी अन्य अपराध के लिए दोषसिद्ध करे
- (c) अभियुक्त व्यक्ति को केवल दोषमुक्त करे
- (d) उपर्युक्त सभी

32) In the proceedings of confirmation of death sentence, the High Court has the right to

- (a) Confirm only the death sentence or pass any other sentence
- (b) Only convict the accused for some other offence.

- (c) Only acquit the accused person
- (d) All of the above

33)निम्न में से कौन-सा वक्तव्य सही नहीं है?(Raj. (CJ) 2013)

- (a) सेशन न्यायालय द्वारा पारित मृत्यु दण्डादेश उच्च न्यायालय द्वारा पुष्टि के विषयाधीन होता है
- (b) सेशन न्यायालय द्वारा पारित मृत्यु दण्डादेश की पुष्टि उच्च न्यायालय द्वारा तब ही की जा सकती है जबकि प्रकरण की सुनवाई कर रही पीठ में कम से कम दो न्यायाधीश हो यदि ऐसे न्यायालय में दो या अधिक न्यायाधीश हो
- (c) अपील प्रस्तुत करने की समयावधि के अवसान के पूर्व मृत्यु दण्डादेश की पुष्टि का आदेश नहीं किया जा सकेगा
- (d) उच्च न्यायालय मृत्यु दण्डादेश की पुष्टि पर विचार करते हुए, यदि अभियुक्त द्वारा उस मृत्यु दण्डादेश को चुनौती देने हेतु अपील नहीं की गई है, तो अभियुक्त को दोषमुक्त नहीं कर सकती है।

33)Which of the following statements is not correct?

- (a) The death sentence passed by the Sessions Court is subject to confirmation by the High Court.
- (b) The death sentence passed by the Sessions Court can be confirmed by the High Court only if there are at least two judges in the bench hearing the case. If such court consists of two or more judges.
- (c) No order for confirmation of the death sentence can be made before the expiry of the time period for presenting the appeal.

(d) The High Court, while considering the confirmation of the death sentence, cannot acquit the accused if no appeal has been filed by the accused challenging the death sentence.

34) ऐसे मामले में, जिनका विचारण सेशन न्यायालय वा मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट द्वारा किया गया है. यथास्थिति, न्यायालय या मजिस्ट्रेट अपने निष्कर्ष और दम्डादेश की हो यदि कोई प्रति अग्रेषित करेगा-(Raj. (CJ) 2013

UP.H.J.S. (P-II) 2018 UP.H.J.S. (P-II) 2018)

(a) उस पुलिस अधीक्षक को, जिसके क्षेत्र में सम्बद्ध अपराध कारित किया गया हो

(b) उस पुलिस थाने को जिसने सम्बद्ध अपराध में अनुसंधान किया हो

(c) उस उच्च न्यायालय को विधारण न्यायालय जिसके अधीनस्थ हो

(d) उस जिला मजिस्ट्रेट को जिसकी स्थानीय अधिकारिता के भीतर विचारण किया गया हो

34) In such cases, which have been tried by the Sessions Court or Chief Judicial Magistrate. The Court or Magistrate, as the case may be, shall forward a copy of his findings and sentence

(a) To the Superintendent of Police in whose area the offence in question has been committed

(b) To the police station which has investigated the offence in question

(c) High Court to which the trial court is subordinate

(d) To the District Magistrate within whose local jurisdiction the trial took place

35) शत्रुधन चौहान बनाम भारत संघ (2014) 3 एस.सी.सी. 1 का वाद किससे संबंधित है?(U.P. A.P.O. 2015)

- (a) न्यायालय के समक्ष झूठी गवाही देने से
- (b) राज्य के विरुद्ध युद्ध छेड़ने से
- (c) फांसी की सजा को आजीवन कारावास में बदलने से
- (d) उपरोक्त में से कोई नहीं

35) Shatrudhan Chauhan vs. Union of India (2014) 3 SCC What is the case of 1 related to?

- (a) By giving false evidence before the court
- (b) By waging war against the state
- (c) By converting the death sentence to life imprisonment.
- (d) None of the above

36) दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 की निम्न धाराओं में से कौन-सी धारा कहती है कि "जब तक अन्यथा उपबन्धित न हो कोई अपील का न होना"?(U.P.A.P.O. 2015)

- (a) धारा 372
- (b) धारा 373
- (c) धारा 375
- (d) धारा 377

36) Which of the following sections of the Code of Criminal Procedure, 1973 says that "no appeal shall lie unless otherwise provided"?

- (a) Section 372
- (b) Section 373
- (c) Section 375
- (d) Section 377

37) दं.प्र.सं.की धारा 372 के तहत पीड़ित ?(U.P. H.J.S. 2012)

- (a) दोषमुक्ति किए जाने के आदेश के खिलाफ अपील दायर कर सकता है
- (b) अपीलीय न्यायालय से अनुमति प्राप्त करने के बाद ही अपील दायर कर सकता है
- (c) अपील दायर करने का कोई अधिकार नहीं है
- (d) अपील दायर करने के लिए जिला मजिस्ट्रेट और लोक अभियोजक से संपर्क करना चाहिए।

37) Under Section 372 of Cr.P.C. a victim?

- (a) can file an appeal against the order of acquittal
- (b) can file an appeal only after obtaining leave from the Appellate Court
- (c) has no right to file an appeal
- (d) should approach the District Magistrate and Public Prosecutor for filing an appeal.

38)दण्ड प्रक्रिया संहिता की किस धारा के अंतर्गत सत्र न्यायाधीश अपनी अपील शक्तियों का प्रयोग करता है?(U.P. A.P.O. 2002)

- (a) धारा 373
- (b) धारा 376
- (c) धारा 397
- (d) धारा 398

38)Under which section of the Code of Criminal Procedure does the Sessions Judge exercise his appellate powers?

- (a) Section 373
- (b) Section 376
- (c) Section 397
- (d) Section 398

39)परिशांति कायम रखने या सदाचार के लिए प्रतिभूति अपेक्षित करने वाले आदेश के विरुद्ध वह व्यक्ति-(M.P.H.J.S. 2019)

- (a) धारा 373 दंड प्रक्रिया संहिता के अंतर्गत सेशन न्यायालय के समक्ष अपील प्रस्तुत कर सकता है
- (b) धारा 397 दंड प्रक्रिया संहिता के अंतर्गत सेशन न्यायालय के समक्ष अपील प्रस्तुत कर सकता है
- (c) धारा 401 दंड प्रक्रिया संहिता के अंतर्गत सेशन न्यायालय के समक्ष पुनरीक्षण आवेदन प्रस्तुत कर सकता है
- (d) तुच्छ प्रकृति का होने के कारण अपील या रिवीजन नहीं की जा सकती

39)A person who, against an order requiring security for the maintenance of peace or good behaviour,-

- (a) Can present an appeal before the Sessions Court under Section 373 of the Code of Criminal Procedure
- (b) Can file an appeal before the Sessions Court under Section 397 of the Code of Criminal Procedure
- (c) Can file a revision application before the Sessions Court under Section 401 of the Code of Criminal Procedure
- (d) Being of frivolous nature cannot be appealed or revised.

40). सत्र न्यायालय दोषसिद्धि के विरुद्ध अपीलीय शक्ति का प्रयोग दण्ड प्रक्रिया संहिता की किस धारा के अंतर्गत करता है?(Uttaranchal (CJ) 2002)

- (a) धारा 372
- (b) धारा 397
- (c) धारा 374
- (d) धारा 398

40). Under which section of the Code of Criminal Procedure does the Sessions Court exercise appellate power against conviction?

- (a) Section 372
- (b) Section 397
- (c) Section 374
- (d) Section 398

41)दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973 की किस धारा के अंतर्गत सत्र न्यायालय धारा 117 और 121 के आदेश के विरुद्ध अपीलीय न्यायालय की शक्ति का प्रयोग करता है?

- a)धारा 372
- b)धारा 373
- c)धारा 374
- d)धारा 375

41) Under which section of the Code of Criminal Procedure 1973, the Sessions Court exercises the power of the Appellate Court against the orders of Sections 117 and 121?

- a) Section 372
- b) Section 373
- c) Section 374
- d) Section 375

42). जबकि भारतीय दंड संहिता की धारा 376 घ के अधीन पारित दंडादेश के विरुद्ध दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 की धारा 374 के अंतर्गत अपील दाखिल की गई है तो, तो अपील का निपटारा होगा -(U.P. (CJ) 2018)****

- (a) ऐसी अपील दाखिल करने की तारीख से 6 माह के भीतर।
- (b) ऐसी अपील दाखिल करने की तारीख से 3 माह के भीतर।
- (c) ऐसी अपील दाखिल करने की तारीख से 9 माह के भीतर।
- (d) युक्तियुक्त अवधि के भीतर।

42). Whereas if an appeal has been filed under Section 374 of the Code of Criminal Procedure, 1973 against the sentence passed under Section 376D of the Indian Penal Code, then the appeal will be disposed of -

- (a) Within 6 months from the date of filing of such appeal.
- (b) Within 3 months from the date of filing of such appeal.
- (c) Within 9 months from the date of filing of such appeal.
- (d) Within a reasonable period.

43) जहां प्रथम वर्ग मजिस्ट्रेट केवल.....रुपये से अनधिक जुर्माने का दण्डादेश पारित करता है, वहां दोषसिद्ध व्यक्ति द्वारा कोई अपील नहीं होगी। (Raj. J.L.O. 2014

M.P. (CJ) 2002

Uttarakhand (CJ) 2008)

- (a) एक सौ
- (b) दो सौ
- (c) तीन सौ
- (c) दो सौ पचास

43) Where a Magistrate of the first class passes a sentence of fine not exceeding..... rupees only, there shall be no appeal by the convicted person.

- (a) one hundred
- (b) two hundred
- (c) three hundred
- (d) two hundred and fifty

44) निम्न मामले में दोषसिद्ध व्यक्ति द्वारा कोई अपील नहीं होगी. (M.P. A.P.O. 1997)

- (a) जहां उच्च न्यायालय केवल छः मास से अनधिक की अवधि के कारावास का दण्डादेश पारित करता है
- (b) जहां सत्र न्यायालय केवल पाँच सौ रुपये से अनधिक जुर्माना का दण्डादेश पारित करता है
- (c) जहां प्रथम वर्ग मजिस्ट्रेट केवल एक मास से अनधिक की अवधि के कारावास का दण्डादेश पारित करता है।
- (d) उपरोक्त सभी दशाओं में

44) There will be no appeal by the convicted person in the following case.

- (a) Where the High Court passes a sentence of imprisonment only for a term not exceeding six months
- (b) Where the Sessions Court passes a sentence of fine not exceeding five hundred rupees only
- (c) Where the First Class Magistrate only passes a sentence of imprisonment for a term not exceeding one month.
- (d) In all the above situations

45) जहां सत्र न्यायालय ने अभियुक्त व्यक्ति को दोषी होने के अभिवचन पर दोषसिद्ध किया है तब (Jharkhand (CJ) 2012)

- (a) वह उच्च न्यायालय में अपील नहीं कर सकता है
- (b) वह उच्च न्यायालय में अपील कर सकता है
- (c) यह अपील केवल दण्ड के परिमाण के बारे में कर सकता है
- (d) वह अपील दण्ड के परिमाण या वैधता के बारे में कर सकता है

45) Where the Sessions Court has convicted the accused person on a plea of guilty, then

- (a) He cannot appeal to the High Court
- (b) He can appeal to the High Court
- (c) It can appeal only about the quantum of punishment
- (d) He can appeal as to the magnitude or legality of the punishment.

46) कथन (A) जहां अभियुक्त व्यक्ति ने दोषी होने का अभिवचन किया है और ऐसे अभिवचन पर दोषसिद्ध किया गया है, वहां कोई अपील नहीं होगी।

कारण (R): कोई व्यक्ति जो जानबूझकर दोषी होने का अभिवचन करता है, दोषसिद्ध किए जाने पर व्यथित नहीं हो सकता है। नीचे दिए गए कूट की सहायता से सही उत्तर चुनिए-

कूट : (U.P. (CJ) 2018)

- (a) (A) और (R) दोनों सत्य हैं तथा (R), (A) का सही स्पष्टीकरण है।
- (b) (A) और (R) दोनों सत्य हैं और (R), (A) का सही स्पष्टीकरण नहीं है।
- (c) (A) सत्य है, किंतु (R) गलत है।
- (d) (A) गलत है, किंतु (R) सत्य है।

46) Statement (A) Where the accused person has pleaded guilty and is convicted on such plea, no appeal shall lie.

Reason (R): A person who knowingly pleads guilty may not be aggrieved at being convicted. Select the correct answer with the help of the code given below-

Code :

- (a) Both (A) and (R) are true and (R) is the correct explanation of (A).
- (b) Both (A) and (R) are true and (R) is not the correct explanation of (A).
- (c) (A) is true, but (R) is false.
- (d) (A) is wrong, but (R) is true.

47)A प्रथम-वर्ग मजिस्ट्रेट द्वारा दोषसिद्ध किया गया और एक माह के कारावास से दण्डित किया गया, क्या A अपील कर सकता है?(Jharkhand (CJ) 2012)

- (a) नहीं A अपील नहीं कर सकता
- (b) A सत्र न्यायालय में अपील कर सकता है
- (c) A मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट के समक्ष अपील कर सकता है
- (d) A उच्च न्यायालय में अपील कर सकता है

47)A is convicted by a first-class Magistrate and sentenced to one month's imprisonment, can A appeal?

- (a) No A cannot appeal
- (b) A can appeal to the Court of Session
- (c) A can appeal before the Chief Judicial Magistrate
- (d) A can appeal to the High Court

48) न्यायिक दण्डाधिकारी प्रथम श्रेणी के न्यायालय द्वारा पारित दोषमुक्ति के आदेश के विरुद्ध अपील होगी: (Uttaranchal (CJ) 2005 Chhattisgarh (CJ) 2003 M.P. (CJ) 19960

- (a) मुख्य न्यायिक दण्डाधिकारी के न्यायालय में
- (b) सत्र न्यायालय में
- (c) उच्च न्यायालय में
- (d) उच्चतम न्यायालय में

48) An appeal against the order of acquittal passed by the Court of Judicial Magistrate First Class shall lie:

- (a) In the court of the Chief Judicial Magistrate
- (b) In the Sessions Court
- (c) In the High Court
- (d) in the Supreme Court

49) यदि किसी दण्डिक अपील में अभियुक्त की मृत्यु हो जाती है एवं उसके नजदीकी रिश्तेदार अपील को जारी रखना चाहते हैं तो उन्हें कितनी अवधि के अंदर आवेदन देना चाहिए?

(Chhattisgarh (CJ) 2004 M.P. (CJ) 1999)

- (a) चार महीने
- (b) तीन महीने
- (c) साठ दिन
- (d) तीस दिन

49) If the accused dies in a criminal appeal and his close relatives want to continue the appeal, then within how much time should they apply?

- (a) four months
- (b) three months
- (c) sixty days
- (d) thirty days

50)मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट द्वारा दोषमुक्ति किए जाने के खिलाफ अपील की जाएगी-(Bihar (CJ) 1999

Chhattisgarh (CJ) 2008)

- (a) सत्र न्यायालय
- (b) उच्च न्यायालय
- (c) वही न्यायालय
- (d) निचली अदालत

50)An appeal against acquittal made by a Metropolitan Magistrate shall lie to-

- (a) The Session Court
- (b) The High Court
- (c) The same Court
- (d) The Lower Court

51)न्यायिक मजिस्ट्रेट द्वारा पारित दोषमुक्ति के निर्णय के विरुद्ध सेशन न्यायालय में अपील की जा सकती है, किसी... अपराध में।(M.P. (CJ) 2012)

- (a) संज्ञेय और अजमानतीय

- (b) संज्ञेय और शमनीय
- (c) असंज्ञेय और अजमानतीय
- (d) असंज्ञेय और जमानतीय

51) An appeal can be made to the Court of Session against the decision of acquittal passed by a Judicial Magistrate in any... offence.

- (a) Cognizable and non-bailable
- (b) Cognizable and compoundable
- (c) Non-cognizable and non-bailable
- (d) Non-cognizable and bailable

52) 'अ' एवं 'ब' का एक साथ विधारण किया जाता है जिसमें 'अ' को जो सजा दी जाती है यह अपील योग्य नहीं है किन्तु 'ब' की सजा अपील योग्य है। क्या 'अ' अपनी सजा के विरुद्ध अपील कर सकता है?(M.P. (CJ) 1999)

- (a) नहीं कर सकता है
- (b) विशेष अनुमति से ही कर सकता है
- (c) कर सकता है
- (d) ऐसा कोई प्रावधान नहीं है

52) 'A' and 'B' are tried together in which the punishment given to 'A' is not appealable but the punishment given to 'B' is appealable. Can 'A' appeal against his sentence?

- (a) can not do
- (b) Can be done only with special permission

- (c) Can do
- (d) There is no such provision

53) एक अपील न्यायालय को अपील का निस्तारण करते समय दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 के अधीन निम्न में से कौन-सा कार्य करने की शक्ति नहीं है?(Raj. A.P.O. 2011)

- (a) दण्ड में वृद्धि नहीं कर सकता जब तक अभियुक्त को ऐसी वृद्धि के विरुद्ध कारण दर्शित करने का अवसर न मिल चुका हो।
- (b) उससे अधिक दण्ड नहीं दे सकता जो अपीलाधीन आदेश पारित करने वाले न्यायालय द्वारा ऐसे अपराध के लिए दिया जा सकता था।
- (c) जब अभियुक्त ने दण्ड की अधिकता के विरुद्ध में अपील की है तो उसे और नहीं बढ़ाया जा सकता उसे, ज्यों का त्यों तो रख सकता है।
- (d) उपरोक्त सभी कार्य।

53)An appellate court, while disposing of an appeal, does not have the power to do which of the following under the Code of Criminal Procedure, 1973?

- (a) Cannot increase the punishment unless the accused has been given an opportunity to show cause against such increase.
- (b) Cannot impose greater punishment than what could have been awarded for such offence by the court passing the order under appeal.
- (c) When the accused has appealed against the excessive punishment, it cannot be increased further, it can be retained as it is.
- (d) All the above actions

54) जहां सत्र न्यायालय ने केवल तीन माह से अधिक की सजा नहीं सुनाई है (Bihar H.J.S. 2016)

- (a) दोषी व्यक्ति द्वारा उच्च न्यायालय के समक्ष अपील की जाएगी
- (b) सजा के बिंदु पर ही अपील उच्च न्यायालय के समक्ष की जाएगी
- (c) एक अपील सर्वोच्च न्यायालय के समक्ष होगी
- (d) उपरोक्त में से कोई नहीं

54) Where a court of session passed only a sentence of imprisonment not exceeding three months.

- (a) an appeal would lie before the High Court by the convicted person
- (b) an appeal would lie before the High Court only on the point of sentence
- (c) an appeal would lie before the Supreme Court
- (d) none of the above

55) एक महानगर मजिस्ट्रेट द्वारा चोरी के एक अभियुक्त को तीन माह के साधारण कारावास व दो सौ रुपये के अर्थदंड से दंडित किया जाता है। अभियुक्त द्वारा उक्त निर्णय की अपील की जा सकती है- (Raj(JS) 2019)

- (a) सेशन न्यायालय में।
- (b) उच्च न्यायालय में।
- (c) मुख्य महानगर मजिस्ट्रेट के न्यायालय में।
- (d) अपील नहीं की जा सकती है।

55) An accused of theft is punished by a Metropolitan Magistrate with three months' simple imprisonment and a fine of two hundred rupees. The said decision may be appealed by the accused-

- (a) In the Court of Session.
- (b) In the High Court.
- (c) In the Court of the Chief Metropolitan Magistrate.
- (d) Cannot be appealed.

56)दोषसिद्धि के बाद धारा 389 (3) दण्ड प्रक्रिया संहिता के अंतर्गत विचारण न्यायालय अभियुक्त को कब जमानत पर छोड़ सकता है....?(M.P. (CJ) 2016 M.P. (CJ) (S-II) 2018)

- (a) जब अभियुक्त जमानत पर हो तथा कारावास तीन वर्ष से अधिक न हो
- (b) जब अभियुक्त जमानत पर हो तथा कारावास पांच वर्ष से अधिक न हो
- (c) जब अभियुक्त जमानत पर हो तथा कारावास चार वर्ष से अधिक न हों
- (d) जब अभियुक्त जमानत पर हो तथा कारावास दो वर्ष से अधिक न हो

56)After conviction, when can the trial court release the accused on bail under Section 389 (3) of the Code of Criminal Procedure?

- (a) When the accused is on bail and the imprisonment does not exceed three years

- (b) When the accused is on bail and the imprisonment does not exceed five years
- (c) When the accused is on bail and the imprisonment does not exceed four years
- (d) When the accused is on bail and the imprisonment does not exceed two years

57) जब उच्च न्यायालय या कोई सत्र न्यायाधीश अपनी अधिकारिता के अधीन किसी अवर दण्ड न्यायालय के समक्ष की किसी कार्यवाही के अभिलेख को परीक्षण करने हेतु मंगाना तो इसे कहा जाता है-(U.P.

(CJ) 2006

Uttaranchal (CJ) 2002)

- (a) निर्देश
- (b) पुनर्विलोकन
- (c) पुनरीक्षण
- (d) उपर्युक्त में से कोई नहीं

57) When the High Court or a Sessions Judge calls for the record of any proceeding before an inferior criminal court under his jurisdiction for examination, it is called -

- (a) reference
- (b) review
- (c) revision
- (d) None of the above

58)निम्नलिखित में से किस न्यायालय को दण्ड प्रक्रिया संहिता की चारा 397 के अंतर्गत अवर दण्ड न्यायालय से अभिलेख मंगाने का अधिकार है?(Raj. J.L.O. 2014)

- (a) उच्च न्यायालय तथा उच्चतम न्यायालय
- (b) सत्र न्यायालय तथा उच्च न्यायालय
- (c) उच्चतम न्यायालय
- (d) उच्चतम न्यायालय, उच्च न्यायालय तथा सत्र न्यायालय

58)Which of the following courts has the right to call for records from the inferior criminal court under Section 397 of the Code of Criminal Procedure?

- (a) High Court and Supreme Court
- (b) Sessions Court and High Court
- (c) Supreme Court
- (d) Supreme Court, High Court and Sessions Court

59)उच्च न्यायालय अथवा सत्र न्यायालय की पुनरीक्षण शक्तियों के प्रयोजन के लिए निम्नलिखित में से कौन-सा अन्तर्वर्ती आदेश है?(Jharkhand (CJ) 2008 M.P. (CJ) (S-II) 2019)

- (a) गवाहों को सम्मन करने वाले आदेश
- (b) मजिस्ट्रेट द्वारा जमानत मंजूर करने का आदेश
- (c) एक ऐसे बिन्दु पर अभियुक्त के अभिवाक को खारिज करने वाला आदेश, जिसे यदि स्वीकार किया जाए तो कार्यवाही- विशेष का ही अन्त हो जाएगा।
- (d) अन्तर्वर्ती आदेश जो क्षेत्राधिकार के बिना है तथा अकृत

59) Which of the following is an interim order for the purpose of revisional powers of the High Court or the Court of Session?

- (a) Orders summoning witnesses
- (b) Order by the Magistrate granting bail
- (c) An order rejecting the plea of the accused on a point which, if accepted, would bring an end to the particular proceeding.
- (d) Interlocutory order which is without jurisdiction and void

60) विधि के किस प्रावधान के अंतर्गत एक सेशन न्यायालय किसी अधिनियम, अध्यादेश अथवा विनियम की विधिमान्यता के संबंध में उच्च न्यायालय को रेफरेंस कर सकता है, जिसका अवधारण मामले को निपटाने के लिए आवश्यक है?(Raj (JS) 2019)

- (a) दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 396
- (b) दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 368
- (c) दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 366
- (d) दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 395

60) Under which provision of law can a Court of Session make a reference to the High Court in respect of the validity of any Act, Ordinance or Regulation, the determination of which is necessary for the disposal of the case?

- (a) Section 396 of the Code of Criminal Procedure
- (b) Section 368 of the Code of Criminal Procedure

- (c) Section 366 of the Code of Criminal Procedure
- (d) Section 395 of the Code of Criminal Procedure

61) आपराधिक प्रक्रिया संहिता की धारा 395 के तहत कौन-सी अदालत संदर्भाधीन मामले पर विचार कर सकती है?(Chhattisgarh (CJ) 2017 Uttarakhand A.P.O. 2010)

- (a) उच्चतम न्यायालय
- (b) विचारण न्यायालय
- (c) सत्र न्यायालय
- (d) उच्च न्यायालय

61) Which court can consider the case under reference under Section 395 of the Code of Criminal Procedure

- (a) Supreme Court
- (b) Trial court
- (c) Sessions Court
- (d) High Court

62) दण्ड प्रक्रिया संहिता के अंतर्गत निम्नलिखित में से कौन सही सुमेलित है?(Uttarakhand (CJ) 2013)

- (a) प्रक्रिया जहां अपीलीय न्यायालय के न्यायाधीश राय के बारे में समान रूप से विभाजित हैं। धारा 392
- (b) अपील पर निर्णयों एवं आदेशों का अंतिम होना। धारा 394
- (c) उच्च न्यायालय को निर्देश-धारा 396
- (d) दोषमुक्ति से अपील में अभियुक्त की गिरफ्तारी-धारा 391

62) Which of the following is correctly matched under the Code of Criminal Procedure?

- (a) Procedure where the judges of the appellate court are equally divided about the opinion. section 392
- (b) Finality of decisions and orders on appeal. section 394
- (c) Instructions to the High Court - Section 396
- (d) Arrest of the accused in appeal from acquittal - Section 391

63) पुनरीक्षण की शक्ति का प्रयोग किया जा सकता है-(Jharkhand (CJ) 2012)

- (a) उच्च न्यायालय द्वारा
- (b) सेशनस न्यायाधीश द्वारा
- (c) अपर सेशनस न्यायाधीश द्वारा, यदि उसे सेशनस न्यायाधीश द्वारा उस मामले का अंतरण किया गया हो
- (d) उपर्युक्त सभी

63) Power of revision can be used -

- (a) By the High Court
- (b) By the Sessions Judge
- (c) By the Additional Sessions Judge, if the case has been transferred to him by the Sessions Judge
- (d) All of the above

64) निम्नलिखित में से कौन-सा उपचार दण्ड प्रक्रिया संहिता में प्रावधानित नहीं है?(U.P.A.P.O. 2015 M.P. A.P.O. 1997 Raj. J.L.O. 2014)

- (a) निर्देश
- (b) पुनर्विलोकन
- (c) पुनरीक्षण
- (d) अपील

64) Which of the following remedies is not provided in the Code of Criminal Procedure?

- (a) reference
- (b) review
- (c) revision
- (d) appeal

65) निम्न में से कौन सही सुमेलित नहीं है?(Uttarakhand (CJ) 2012)

- (a) उच्च न्यायालय को निर्देश
- धारा 395
- (b) उच्च न्यायालय की पुनरीक्षण की शक्तियां
- धारा 401
- (c) अपीलों का उपशमन
- धारा 393
- (d) दोषसिद्धि से अपील
- धारा 374

65) Which of the following is not correctly matched?

- (a) Reference to the High Court
- Section 395
- (b) Powers of revision of the High Court

- Section 401
- (c) Abatement of appeals
- Section 393
- (d) Appeal from conviction
- Section 374

66) दण्ड प्रक्रिया संहिता के अधीन, उच्च न्यायालय अपनी पुनरीक्षण शक्ति का प्रयोग करते हुए-(U.P. (CJ) 2013)

- (a) अभियुक्त का उन्मोचन नहीं कर सकता है।
- (b) अभियुक्त को दोषमुक्त नहीं कर सकता है।
- (c) अभियुक्त को जमानत नहीं दे सकता है।
- (d) दोषमुक्ति के निष्कर्ष को दोषसिद्धि के निष्कर्ष में संपरिवर्तित नहीं कर सकता है।

66) Under the Code of Criminal Procedure, the High Court, in the exercise of its revisional power-

- (a) Cannot discharge the accused.
- (b) Cannot acquit the accused.
- (c) Cannot grant bail to the accused.
- (d) Cannot convert a finding of acquittal into a finding of conviction.

67) दं.प्र.सं.की धारा 125 के तहत पारित आदेश को असफल पक्ष द्वारा पुनरीक्षण दायर करके चुनौती दी जा सकती है-

- (a) केवल मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट के समक्ष
- (b) केवल सत्र न्यायाधीश के समक्ष
- (c) केवल उच्च न्यायालय के समक्ष

(d) या तो सत्र न्यायाधीश या उच्च न्यायालय के समक्ष।

67) An order passed under Section 125 of Cr.P.C can be challenged by the unsuccessful party by filing a revision-

- (a) only before Chief Judicial Magistrate
- (b) only before Sessions Judge
- (c) only before High Court
- (d) Either before the Sessions Judge or High Court.

68) दं.प्र.सं की धारा 145(6) के तहत सब डिविजनल मजिस्ट्रेट द्वारा पारित आदेश के खिलाफ पुनरीक्षण दायर किया जा सकता है। के न्यायालय में-(U.P.H.J.S. 2012)

- (a) जिला मजिस्ट्रेट
- (b) एडीएम (प्रशासन)
- (c) मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट
- (d) सत्र न्यायाधीश

68)A revision can be filed against an order passed by Sub Divisional Magistrate under Section 145(6) of Cr.P.C. in the Court of-

- (a) District Magistrate
- (b) ADM (Administration)
- (c) Chief Judicial Magistrate
- (d) Sessions Judge

69) आपराधिक प्रक्रिया संहिता के अध्याय 30 में क्या शामिल है?

- (a) धारा 372 से 394
- (b) धारा 395 से 405
- (c) धारा 370 से 380
- (d) धारा 394 से 404

69) Chapter 30 of criminal procedure code covers ?

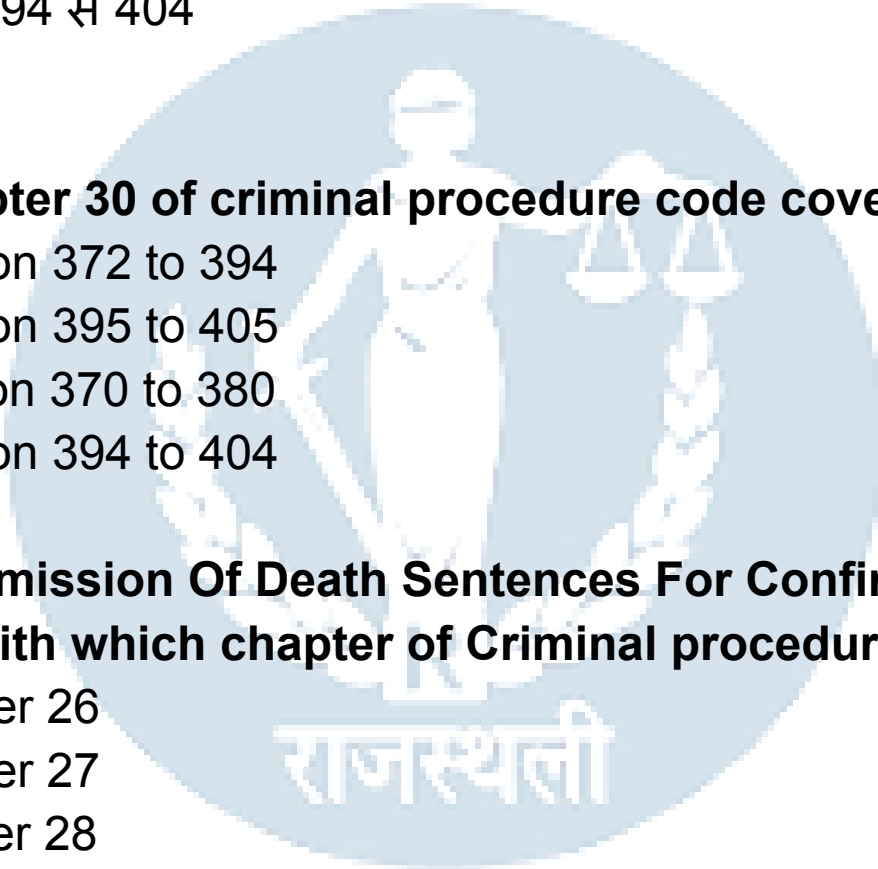
- (a) Section 372 to 394
- (b) Section 395 to 405
- (c) Section 370 to 380
- (d) Section 394 to 404

70) Submission Of Death Sentences For Confirmation Deals with which chapter of Criminal procedure code?

- a) Chapter 26
- b) Chapter 27
- c) Chapter 28
- d) Chapter 29

70) मृत्युदंड की पुष्टि के लिए प्रस्तुत करना आपराधिक प्रक्रिया संहिता के किस अध्याय से संबंधित है?

- a) अध्याय 26
- b) अध्याय 27
- c) अध्याय 28
- d) अध्याय 29



RAJASTHALI
LAW INSTITUTE

Answer key

1-d

2-b

3-d

4-b

5-c

6-d

7-b

8-b

9-c

10-b

11-c

12-d

13-c

14-b

15-d

16-c

17-c

18-c

19-d

20-d

21-b

22-c



ESTD 2003
RAJASTHALI
LAW INSTITUTE

23-b
24-d
25-b
26-d
27-c
28-d
29-b
30-d
31-d
32-d
33-d
34-d
35-c
36-a
37-a
38-a
39-a
40-c
41-b
42-a
43-a
44-a
45-d
46-a
47-b
48-b
49-d



ESTD 2003
RAJASTHALI
LAW INSTITUTE

50-a

51-a

52-c

53-c

54-d

55-d

56-a

57-c

58-b

59-b

60-d

61-d

62-a

63-d

64-b

65-c

66-d

67-d

68-d

69-b

70-c



ESTD 2003

RAJASTHALI

LAW INSTITUTE